



## INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 2 Jan; Issue 1 Mar; 2024; Page No. 543-548

### ग्रामोत्थान एवं संचार (स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात्- एक मूल्यांकन)

डॉ. (श्रीमती) नीरज

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, कुरावली, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, भारत

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15664190>

Corresponding Author: डॉ. (श्रीमती) नीरज

#### सारांश

ग्रामीण विकास प्रक्रिया में संचार की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। आज भारत में ग्रामीण विकास के लिए संचार के सभी साधन अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण विकास के लिए सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा गैर सरकारी सेवाएँ, जैसे सामुदायिक विकास विभाग, समाज कल्याण बोर्ड, भारत सेवक समाज तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि प्रयत्नरत हैं। संचार साधनों की सूचना के अनुसार तीन क्षेत्र दृष्टिगत होते हैं। प्रथम, वह क्षेत्र जो कार्य की दृष्टि से अभी अछूता है, दूसरा, वह क्षेत्र जहाँ वर्षों से कार्य हो रहा है और कुछ उल्लेखनीय विकास हुआ है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण विकास का प्रारम्भ वर्ष 1901 में सिंचाई आयोग के रूप में हो चुका था इस विकास की व्यार को आगे बढ़ाते हुए 1921 में डॉ० स्पेन्सर हैच के नेतृत्व में भारतपंडम की रक्षापना भी ग्रामीण जनों के आर्थिक विकास के लिए की गयी थी। इस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से संचार साधनों ने भरपूर सहयोग प्रदान किया और आयोगों एवं संगठनों से ग्रामीणों को अवगत कराकर अपनी अहम भूमिका निभाई। संचार साधनों में समाचार पत्र, रेडियो, संगठन, गांव की पाठशाला, पुस्तकालय, पंचायत एवं प्रशिक्षण इत्यादि ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। स्वतंत्रता के पश्चात् भी इन संचार साधनों द्वारा सरकारी योजनाओं को पूरा करने में सहयोग किया गया। वर्तमान में संचार के साधनों में वृद्धि हुई है। जैसे टेलीविजन, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, ई-मेल इत्यादि। सभी संचार साधनों की भूमिका समय के अनुसार व स्थितियों, उपलब्ध साधनों के कारण बदलती रहती है।

**मूल शब्द:** ग्रामोस्थान, संचार, स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात्, इतिहास, संचार साधन।

#### प्रस्तावना

हमारे देश की विद्यमान आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों में ग्रामीण विकास की अनिवार्यता निर्विवाद है। भारतीय अर्थतन्त्र की द्वियात्मक प्रादेशिक संरचना जो प्रमुखतः औपनिवेशिक काल की विरासत है। निश्चित रूप से स्वतंत्रतयोत्तर काल में प्रखर हुई है। इसका मुख्य कारण कृषि प्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण अधिवासों का पिछड़ापन तथा उन पर समुचित ध्यान का अभाव है परन्तु इन सभी समस्याओं का निवारण करने में संचार साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है।

भारत की मूल संस्कृति ग्रामीण है। बहुसंख्यक लोगों का सम्बन्ध ग्रामीण परिवेश से है। इस कारण ग्रामीण समुदाय में संचार की प्रवृत्ति को जानना आवश्यक है। भारत के अतिरिक्त विश्व के विकसित से भी विकसित देश के सम्बन्ध में विचार करें तो स्पष्ट होगा कि वहाँ का भी समुदाय ग्रामीण एवं नगरीय भागों में विभक्त है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृति विश्व के प्रत्येक देश या समुदाय की विशेषता है। विश्व की समस्त जानकारी हमें संचार के माध्यमों से प्राप्त होती रहती है।

ग्रामीण विकास प्रक्रिया में संचार की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। आज भारत में ग्रामीण विकास के लिए संचार के सभी साधन अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण विकास के लिए सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाएँ, जैसे सामुदायिक विकास विभाग, समाज कल्याण बोर्ड, भारत सेवक समाज तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि प्रयत्नरत हैं।

संचार साधनों की सूचना के अनुसार वर्तमान समय में समग्र विकास की दृष्टि से ग्राम इकाई योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्य के सिंहावलोकन से तीन क्षेत्र सामने लाते हैं-

- वह क्षेत्र जो कार्य की दृष्टि से अभी अछूता है,
- वह क्षेत्र जहाँ इस योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ हुआ है किन्तु विकास प्रारम्भिक अवस्था में है,
- वह क्षेत्र जहाँ वर्षों से कार्य हो रहा है और कुछ उल्लेखनीय विकास हुआ है।

ग्रामीण विकास के स्तर को भली भाँति जानने के लिये संचार माध्यमों का तथा ग्रामीण विकास के सम्बन्धों का अध्ययन स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के बाद, दोनों पहलुओं को लेकर

करेंगे जिससे प्रारम्भ से अब तक की ग्रामीण विकास व संचार साधनों की स्थितियों का अध्ययन किया जा सके।

### **भारत में ग्रामीण विकास व संचार का इतिहास**

संचार एवं विकास का आपस में सम्बन्ध स्वतन्त्रता से पूर्व और स्वतन्त्रता के पश्चात् के अध्ययन से ओर भी स्पष्ट हो जायगा—

**(अ) स्वतन्त्रता से पूर्व—** भारत में राजकीय प्रक्रिया के रूप में ग्रामीण विकास का आरम्भ वर्ष 1901 में सिंचाई आयोग के रूप में हो चुका था। इसकी वृद्धि का फिर सामान्य प्रयास 1927 में शही कृषि आयोग तथा 1932 में खाद्य उत्पादन के गठन से किया गया। ग्रामीण विकास के पुनः निर्माण हेतु 1921 से 1930 तक का दशक इस दिशा में सारांशतः महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि 1921 में श्री रविन्द्र नाथ टैगोर द्वारा श्री निकेतन इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल री-कन्सट्रक्शन स्थापित किया। इसके निर्देशक एम० हस्ट ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। 1921 में डॉ० स्पेन्सर हैच के नेतृत्व में भारतप्लॉम की स्थापना भी ग्रामीण जनों के आर्थिक विकास के लिए की गयी। 1927 में गुडगाँव प्रयोग ब्रेन द्वारा प्रारम्भ किया गया।

इसमें ग्रामीण विकास के विभिन्न पक्षों, कृषि संसाधन, संगठन और स्थानीय विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया यद्यपि यह विचारधारा उत्तम रही लेकिन शासकीय एवं उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं ने इसमें सहयोग नहीं दिया। परन्तु उस समय में प्रचलित संचार साधनों ने इसका भरपूर साथ दिया व भारतीय जनता को इन आयोगों एवं संगठनों से अवगत कराकर ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका सिद्ध की।

**इन संचार साधनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है जो निम्न प्रकार से हैं—**

**1. समाचार पत्र—**समाचारों को बिक्री के लिये वितरण करने की तारीख तो ज्ञात नहीं है, किन्तु यह पुनर्जागरण काल (Renaissance) से मानी जाती है। जैसे—जैसे शहरों का विकास हुआ तो यूरोप में व्यापार का फैलाव हुआ, तब लोगों को आवश्यकता अनुभव होने लगी कि सुदूर स्थानों पर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी उन्हें मिलती रहे लेकिन जो मुद्रक थे (इन्हें हम अब पत्रकार कह सकते हैं), वे कभी—कभी इधर—उधर जाने वाले यात्रियों के माध्यम से समाचार—सूचनायें भिजवाते थे तथा अपने ग्राहकों को “समाचार चौपन्ने” (News pamphlets) देते थे। ये ‘समाचार चौपन्ने’ अनियतकालीन हुआ करते थे। जब यात्री जाते थे, तभी ही दूर स्थानों तक सूचनायें पहुँचती थी। सन् 1622 में लन्दन में एक दर्जन मुद्रक थे, जिन्होंने नियमित रूप से पत्रों के आदान—प्रदान का सिलसिला शुरू किया और इस प्रकार वे साप्ताहिक पत्र निकालने में सफल हुए।

आरम्भ में वे मुख्य रूप से विदेशी समाचारों से ही मतलब रखते थे, किन्तु धीरे—धीरे उन्होंने घेरेतू राजनीति को भी स्थान देना शुरू कर दिया, जो बहुत जटिल हो चुकी थी तथा जिसे सामान्य नागरिक के लिए शब्दों में व्यान करना कठिन था। अब स्थितियाँ दैनिक समाचार पत्र निकालने के लिए अनुकूल हो गई, और इस तरह इस वातावरण में सन् 1702 ई० में लन्दन से पहला दैनिक ‘Daily Courant’ अस्तित्व में आया।

हमारे देश में प्रेस अंग्रेजों के आगमन के बाद अस्तित्व में आया। उन्होंने कलकत्ता के उपनगर श्रीरामपुर में धर्म प्रचार के उद्देश्य से मुद्रणालय खोला, किन्तु पहला समाचार पत्र ‘बंगाल गजट ऑफ कलकत्ता जनरल एडवरटाईजर’ नाम से 21 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ। यह पत्र अंग्रेज सज्जन जेम्स आगस्ट हिकी की मेहनत का प्रतिफल था। यह प्रथम ऐतिहासिक भारतीय समाचार पत्र था, जिसमें हिकी ने मन और आत्मा की स्वतन्त्रता का आग्रह

किया।

भारत के स्वतन्त्र होने से पहले भारत छोटी—छोटी रियासतों में बँटा था। अंग्रेजी शासन होने के कारण भारत का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा था लेकिन इस अंग्रेजी शासन के रोकने के बाद भी जो विकास हो रहा था वह संचार के कारण हो रहा था जिसमें समाचार पत्रों की अहम भूमिका थी। भारतीय लोग परतन्त्र थे तथा अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य नहीं कर सकते थे लेकिन लोगों में एक नई जागृति लाने का कार्य उस समय समाचार पत्रों या अखबारों का था जब अखबार के सहारे ही नेता व समाज सुधारक गाँवों में विकास के साधनों को बताते थे। गाँव की दशा में सुधार व लोगों के जीवन को सुधारने का कार्य प्रेस निभा रही थी। स्वतन्त्रता से पहले लोगों तक संचार का साधन प्रेस ही था जो अन्य क्षेत्रों के साथ—साथ गाँव की स्थिति में सुधार व विकास का कार्य भी कर रही थी।

**2. रेडियो—** रेडियो का आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ। वास्तव में रेडियो की कहानी सन् 1815 ई० से आरम्भ होती है जब इटली के एक इंजीनियर गुग्लियो मार्कोनी ने रेडियो टेलीग्राफी के जरिए पहला सन्देश प्रसारित किया। यह सन्देश ‘मार्स कोड’ के रूप में था। रेडियो पर मनुष्य की आवाज पहली बार सन् 1906 में सुनाई दी। यह तब सम्भव हुआ जब अमेरिका के ली० डी० फारेस्ट ने प्रयोग के तौर पर एक प्रसारण करने में सफलता प्राप्त की। उसने एक परिष्कृत निर्वात नलिका का आविष्कार किया, जो आने वाले संकेतों के विस्तार देने के लिए थी। डी फारेस्ट ही था, जिसने सर्वप्रथम सन् 1916 में पहला रेडियो समाचार प्रसारित किया। यह समाचार वास्तव में संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम की रिपोर्ट थी। सन् 1920 के बाद तो अमेरिका और ब्रिटेन ही क्या, विश्व के कई देशों में रेडियो ने धूम मचा दी।

इसी अवधि में यूरोप, अमेरिका तथा एशियाई देशों में बहुत से शोधकार्य हुए थे। इन शोधकार्यों के फलस्वरूप रेडियों ने अभूतपूर्व प्रगति की। कालान्तर में इलैक्ट्रॉन तथा ट्रांजिस्टर की खोज ने रेडियो—ट्रॉजिस्टर तथा दूरसंचार के क्षेत्र में बहुत विकास किया।

स्वतन्त्रता से पूर्व रेडियो प्रसारण का प्राथमिक उद्देश्य था—मनोरंजन। द्वितीय रूप से विदेशी समाचारों से ही मतलब रखते थे, किन्तु यह स्थान पर थी—शिक्षा। यह एक संघर्षपूर्ण शुरूआत थी। रेडियो के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाता था और ग्रामीण लोगों के लिए रेडियो का महत्व अत्याधिक था, क्योंकि खेती की शिक्षा, उद्योगों के बारे में छोटी—मोटी जानकारी, बाहरी वातावरण का परिचय तथा भारतीय लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य रेडियो कर रही थी। यह कहा जा सकता है कि उस समय सब लोगों के पास रेडियो उपलब्ध नहीं थी लेकिन रेडियो जहाँ—जहाँ थी वहाँ वह लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेती थी, रेडियो पर जो जानकारी ग्रामीण लोग पाते थे, उसके बाद वे आपस में उस विषय पर चर्चा करते थे जिससे उन्हें विभिन्न जानकारी अपने गाँव में बैठे—बिठाए मिल जाती थी। गाँव की जरूरतों व सरकार द्वारा प्रस्तुत गाँव के सुधार के कार्यक्रम भी जनता तक जाते थे। जिससे सभी लोग परिचित रहते थे कि अब किस विकास या किस समस्या पर विचार विमर्श हो रहा था। उस समय रेडियो एक नया साधन था और कुछ लोगों के पास ही था जिससे लोगों ने रेडियो के कार्यक्रम सुनने का उत्साह भी रहता था। इसलिये कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता से पूर्व रेडियो ने ग्रामीण परिवेश व विकास पर बहुत प्रभाव डाला था जो भारत की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था।

**3. संगठन—** स्वतन्त्रता से पूर्व सामुदायिक विकास एवं सामाजिक सुरक्षा की भावना का समावेश था और इनके सफल संचालन हेतु एक सुदृढ़ संगठन की आवश्यकता होती थी जो शोषणमुक्त,

वर्गविहीन, अहिंसक समाजवादी, समाज की स्थापना में पूर्णतः समर्थ हों और जो ग्रामीण जीवन को, जो समग्र के साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में परावलम्बी बना सके और जो सामुदायिक सहयोग एवम् सद्बयवहार के आधार पर स्वावलम्बन की ओर ले जाने में समर्थ हो। उस समय में ग्रामीण लोग अपना विकास संगठन के माध्यम से करते थे। उस समय अंग्रेजों का शासन था और लोगों का विकास सम्भव हो पाना काफी मुश्किल हो रहा था लेकिन संगठन उस समय एक अच्छे संचार का माध्यम साबित हो रहा था जो लोगों की सुरक्षा व विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था।

**4. गाँव की पाठशाला—** गाँव को विकासोन्मुख करने के लिये स्वतन्त्रता से पूर्व गाँव की पाठशालाओं का सहारा लिया जाता था। जिन विचारों को लोगों तक पहुँचाना होता था उन विचारों को सर्वप्रथम स्कूल—संस्था तक ही पहुँचाया जाता था। स्कूल ग्राम—संस्थाओं की उस तिपाई का तीसरा चरण है जिस पर नव भारत की सुदृढ़ इमारत खड़ी करने की बात सोची जा रही थी। इनका उद्देश्य था कि ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में एक प्रकार का कायापलट कर देना। विद्यालय में स्थानीय और पड़ौसी गाँव के अधिकांश परिवारों के बच्चे इकट्ठे होते थे। उनका यह समुदाय शिक्षक को भी सहज ही उपलब्ध हो जाता था इनके सहारे गाँव में संचार कार्य आराम से चलाया जाता था। इसके अलावा विद्यालय में और भी कार्यक्रम होते थे—

1. समय—समय पर निकासी आयोजित प्रभात फेरियाँ, जुलूस और नारे,
2. गाँव के चौराहों और घरों की साफ दीवारों पर सूक्तियाँ लिखना,
3. स्कूल संग्रहालय, जिसमें गाँव के प्राकृतिक साधनों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी वनौषधियाँ तथा तृण आदि का संग्रह किया जाता था जिससे गाँव के लोगों को मिट्टी की जानकारी दी जाती थी।

**5. ग्रामीण विकास में संचार साधन के रूप में पुस्तकालय का स्थान:** पुस्तकालय स्वयं कोई साध्य नहीं है, वह साध्य के लिए एक साधन मात्र है। उद्देश्य साधन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। बहुत प्राचीन काल से ही पुस्तकालय, शिक्षा और ज्ञानार्जन का एक बहुत बड़ा साधन माना गया है। किसी देश का विकास सचमुच पुस्तकालय की जीवित प्रणाली से हो सकता है। पुस्तकालय में पाठक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बौद्धिक विकास के लिए व्यक्ति को नये व पुराने विचारों को जानना जरूरी है और ये विचार पुस्तकों से ही जाने जा सकते हैं। स्वतन्त्रता से पूर्व भी लोगों को किताबों से काफी जानकारी मिल जाती थी और फिर वह जानकारी लोगों तक पहुँच जाती थी। जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के तथा अनपढ़ थे वे भी दूसरे पढ़े—लिखे लोगों से विकास सम्बन्धी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते थे। इसलिये यह स्पष्ट है कि किताबों व पुस्तकालयों का महत्व स्वतन्त्रता के पूर्व भी काफी था। पुस्तकालय द्वारा समान शिक्षा, स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न, विचार का आदान—प्रदान, तथा संचार का आदान—प्रदान आसानी से किया जा सकता था। उस समय भूदान—ग्राम आन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनों को सफल बनाने में संचार के साधनों का महत्व था और पुस्तकों का विशेष महत्व था जो जनता को अहिंसक आन्दोलनों से जोड़ रही थी।

**6. ग्रामीण संचार में ग्राम पंचायत की भूमिका—** स्वतन्त्रता से पूर्व भी पंचायत को एक अच्छे संचार साधन के रूप में माना जाता था। भारत के प्राचीन इतिहास का सिंहावलोकन करने से विदित

होता है कि आदिकाल में भी भारतीय संस्कृति काफी उन्नत अवस्था में थी। तत्कालीन समाज एवं संस्कृति तथा आर्थिक व सामाजिक स्थिति कुछ अर्थों में वर्तमान की अपेक्षा अत्याधिक प्रगतिगमी थी। शासन व सत्ता की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि एकत्रीय शासन होते हुए भी उसमें प्रजातन्त्र की झलक प्रतीत प्रारम्भ होती थी। शासन की प्रारम्भिक इकाई गाँव से ही प्रारम्भ होती थी, जिसे ग्राम पंचायत कहते थे, जो कि गाँव से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने में सक्षम थी।

**7. प्रशिक्षण—** किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उपयुक्त कार्यकर्ताओं का निर्माण किया जाये। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के अभाव में किसी भी विकास या योजना की सफलता सम्भव नहीं है। ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए स्वतन्त्रता से पूर्व कुछ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था जो गाँव के गरीब व अनपढ़ लोगों को ग्रामीण विकास सम्बन्धी जानकारी देते थे। उस समय सभी लोगों को प्रशिक्षित करना सम्भव नहीं था। प्रशिक्षण के द्वारा लोगों को कुछ हद तक सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय सुलभ करवाने की कोशिश की जाती थी। गाँव की आर्थिक व सामाजिक स्थिति के अनुसार सुधार सम्बन्धी कार्यों को अन्जाम देने के लिए भी प्रशिक्षण देने की कोशिश की जाती थी लेकिन यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती थी क्योंकि अंग्रेजों के शासन से भारतीयों को ग्रामीण विकास सम्बन्धी साधन सुलभ नहीं हो पाते थे किन्तु जितना भी उनसे प्रयत्न होता था वह ग्रामीण विकास के लिए करते थे। अतः प्रशिक्षण प्रणाली एक प्रकार से विचारों का आदान—प्रदान करने में संचार रूपी भूमिका निभा रही थी।

स्वतन्त्रता से पूर्व संचार के साधनों में समाचार पत्र, रेडियो, संगठन, गाँव की पाठशाला, पुस्तकालय, ग्राम पंचायतें व प्रशिक्षण थे जो ग्रामीण विकास में अपनी—अपनी भूमिका निभाने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन कोई भी साधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसे पूरी सहायता न प्राप्त हो। स्वतन्त्रता से पूर्व वैसे भी भारतीय गुलामी का जीवन बिता रहे थे इसलिये ये संचार साधन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में असमर्थ थे लेकिन फिर भी जो भी जानकारी ग्रामीण जनता तक पहुँच रही थी वह इन्हीं संचार माध्यमों के द्वारा पहुँच रही थी और इन्हीं से ग्रामीण विकास में थोड़ी—बहुत सहायता मिल रही थी।

**(ब) स्वतन्त्रता के पश्चात्—** स्वतन्त्रता के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया तथा अनेक समयबद्ध कार्यक्रम अपनाये गये जैसे— '2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक कार्यक्रम आरम्भ किया गया, इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विपणन सेवाओं के विस्तार का लक्ष्य मुख्य रहा। इसके पश्चात् सन् 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा (National Extension Service) को व्यवस्थित कर विकास खण्डों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई ताकि क्षेत्र स्वतः संसाधनों द्वारा विकसित हो सकें' परन्तु कार्यक्रम का अव्यवस्थित स्वरूप आशानुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहा। सन् 1960 में खाद्यान्न की कमी से ग्रामीण विकास के रूप में कृषि विकास को प्रस्फुटित किया गया जबकि विकास के अन्य पक्षों पर कम ध्यान रहा, परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र एकांकी हो गया और उसमें भी पूर्ण सफलता नहीं मिली। स्वतन्त्रता के पूर्व तो सीमित रूप से संचार कार्य करता था लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात् संचार साधन भी स्वतन्त्र रूप से कार्य करने लगे हैं। अब हम देखेंगे कि स्वतन्त्रता के पश्चात् संचार साधनों की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है तथा ये कहाँ तक सहायता करते हैं—

**1. समाचार पत्र या प्रेस—** स्वतन्त्रता के बाद तो समाचार पत्रों के

प्रकाश में एक साथ प्रगति हुई। सैकड़ों समाचार पत्र निकलने आरम्भ हुए। इनका कारबाँ आज भी चल रहा है। अब तो इनकी संख्या हजारों में है। भारत में प्रारम्भ में नई सूचना प्रौद्योगिकी के ग्रहण करने की रफ्तार धीमी थी लेकिन वह निरन्तर प्रगति की ओर है। सन् 1950 से 2006 तक के वर्षों में प्रेस, रेडियो, एवं फिल्म की पहुँच 15 प्रतिशत से भारतीय आबादी से बढ़कर 65 प्रतिशत पर पहुँच गई है।

**समग्रतः** हम देखते हैं कि प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरोध में सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में, साहित्यिक-सांस्कृतिक जागरण में, प्रिसुप्त जनता में राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस जनसंचार माध्यम ने देश के कोने-कोने में लोगों को देश की परिस्थितियों से अवगत कराया। इस सन्दर्भ में हम डॉ अम्बेडकर के "मूकनायक" पत्र का भी उल्लेख करना जरुरी समझते हैं जिसने जनता को उसके देश के पिछड़पन को बताया।

ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वे सेवाएँ एवं सुविधाएँ सम्प्रिलित हैं जो आर्थिक स्वरूप के सम्यक् विकास के लिये अति आवश्यक होती है तथा जिसकी पूर्व जानकारी अखबारों से ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्राप्त करते हैं। अखबारों की जानकारी से आर्थिक स्वरूप ही नहीं, वरन् सम्बद्ध रूप से सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक विकास भी सम्भव है लेकिन यह निर्विवाद है कि मानवीय संसाधनों के गुणात्मक पहलू को सुदृढ़ बनाने में शिक्षा की अहम् भूमिका होती है। समाचार पत्र ही हमें शैक्षिक व्यवस्था, शैक्षिक सुविधाओं व योजनाओं का पूरा ब्लौरा देते हैं। यह ही नहीं, अखबारों ने नई वैज्ञानिक खोजों, स्वास्थ्य की पूरी जानकारी अनुसंधानों का पूरा वर्णन ग्रामीण जनता तक समाचार पत्रों के द्वारा ही पहुँचता है तथा जिसका पूरा फायदा उठाकर अपना विकास करने में ही ग्रामीण लोग चूकते नहीं।

ग्रामीणों का आर्थिक स्वरूप मुख्यता कृषि पर ही आधारित है। चाहे ग्रामीण जनता अपने लिए शहरों जैसी सुख-सुविधाओं की कल्पना भले ही न करें इसकी अपनी कुछ वाजिब आकांक्षाएँ जरूर हैं जैसे उपजों हेतु बाजार एवं कीमतों की जानकारी, भूमि सम्बन्धी एवं अन्य रिकार्डों का आसानी से उपलब्ध होना, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा, सामाजिक न्याय आदि सूचना देने में समाचार पत्र मदद करते हैं। क्षेत्र का विकास बहुत अंशों तक कृषि के विकास पर निर्भर है, जिसके लिए कृषि प्रस सेवाओं के स्तर एवं स्थिति का उचित निर्धारण नितान्त आवश्यक है। इन सभी स्तरों की जानकारी ग्रामीण समाचार पत्रों से भी काफी हद तक प्राप्त कर लेते हैं जिससे आज की कृषि व्यवस्था विकास की और दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं यह ही नहीं अपनी फसलों के अच्छे दाम कहाँ से प्राप्त करें यह भी समाचार पत्र बताने में मदद करता है। आज शहरों में ही नहीं ग्रामों में भी समाचार पत्र मूल आवश्यकता बन गयी है क्योंकि यह विकास का सीधा व सस्ता साधन है जो आराम से ही सुलभ हो जाता है।

**2. रेडियो-** स्वतन्त्रता के बाद से "आकाशवाणीऑल इण्डिया रेडियो" का व्यापक प्रसार हुआ है। सन् 1947 में जहाँ पूरे देश में मात्र 6 प्रसारण केन्द्र, एक दर्जन ट्रांसमीटर और दो-ढाई लाख रेडियो सेट थे, वहीं आज हमारे पास 100 से अधिक रेडियो स्टेशन हैं जो देश के तीन-चौथाई से अधिक भौगोलिक क्षेत्र तथा 90 प्रतिशत के लगभग जनसंख्या को अपनी प्रसारण सीमा में लिए हुए हैं और इस जनसंख्या पर रेडियो के द्वारा जो विकास सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका काफी प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वतन्त्रता के बाद से सरकार ने ज्यादातर ग्रामीणों की स्थिति में सुधार के लिये रेडियो सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत करवाये जिससे जो विकास शहर का हो रहा है उसी की तरह

ग्रामों का भी विकास हो। आज यह संचार का एक अच्छा साधन है जो लोगों को घर बैठे-बिठाये ही सारी जानकारियाँ उपलब्ध करा देता है। विकास की सब योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुँचाने की आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसका परिणाम यह हुआ कि जो विकास स्वतन्त्रता पूर्व सुप्त अवस्था में पड़ा था वह स्वतन्त्रता के पश्चात् धीरे-धीरे तेज होता जा रहा था। ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कुछ कार्यक्रम आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत किये जाते थे जैसे किसान, भाईयों का कार्यक्रम, सैनिक भाईयों का कार्यक्रम, कुछ और कार्यक्रम जो गाँव के विकास में सहायक थे और जो आगे चलकर नींव का पथर साबित हुए क्योंकि आकाशवाणी के कार्यक्रम जनता को अधिक से अधिक जानकारी देना चाहते थे और अपनी इसी लोकप्रियता के कारण आकाशवाणी का महत्व बढ़ता जा रहा था। इसका एक प्रमुख कारण और भी था कि इसे अनपढ़ व निरक्षर लोग भी सुन सकते थे क्योंकि इसमें लोग आवाज सुनते थे जिसमें शिक्षित व अशिक्षित से कोई सम्बन्ध नहीं था। अपनी इस विशेषता के कारण यह सभी लोगों की आवश्यकता सी बनती जा रही थी। अनपढ़ लोग भी देश में क्या हो वह उनके क्या कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति जानने लगे थे और वे अपने देश की सहायता कैसे कर सकते हैं, यह सब जानकारी लोग रेडियो से प्राप्त करने लगे। यह ऐसा संचार माध्यम था जो, बच्चे व बड़े, अमीर-गरीब, शिक्षित व अशिक्षित, शहरी व ग्रामीण सभी के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।

**3. संगठन-** स्वतन्त्रता के पश्चात् आज भारत में ग्रामीण विकास के लिए सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाएँ जैसे सामुदायिक विकास विभाग, समाज कल्याण बोर्ड, भारत सेवक समाज तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इनके अन्तर्गत रचनात्मक क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने सारे देश में सघन क्षेत्र योजना आरम्भ की इससे प्राप्त अनुभवों के आधार पर सन् 1960 में ग्राम इकाई योजना का रूप सामने आया, जो आज खादी ग्रामोद्योग आयोग की व्यापक तथा महत्वपूर्ण योजना है। इसी का दूसरा नाम समग्र ग्राम विकास योजना है।

जहाँ तक नये क्षेत्रों का सम्बन्ध है, इस योजना के अन्तर्गत प्रथम क्षेत्र में ग्रामसमाज, ग्राम पंचायत या बहुधंधी सहकारी समिति अथवा ग्रामदानी गाँवों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समग्र विकास की दृष्टि से ग्राम इकाई कार्य का संगठन किया जाये। दूसरे क्षेत्र वे हैं जहाँ ग्राम इकाई के अन्तर्गत कार्य हो रहा है वहाँ भी ग्रामदान की भूमिका में ग्राम इकाई का संगठन किया जाये। तीसरे प्रकार के क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से खादी ग्रामोद्योग, उत्पादन व बिक्री कार्य चल रहा है। उस क्षेत्र में विविध कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वावलम्बन वृत्ति की दिशा में इकाई कार्य का संगठन किया जाय और अप्रयुक्त मानव शक्ति, प्राकृतिक साधन स्रोतों का उपयोग कर आर्थिक विकास किया जाये। आज इकाई का गठन दो रूपों में किया जा रहा है, प्रथम-न्याय पंचायत के स्तर पर अथवा पाँच हजार आबादी वाले क्षेत्र में तथा दूसरा-विकास खण्ड के स्तर पर।

**4. गाँव की पाठशाला-** स्कूल ही आज आधुनिक सभ्यता की वाहक संस्था मानी जाती है। जिस क्षेत्र में आधुनिक विचारों के प्रसार की बात सोची जाती है, वहाँ सर्वप्रथम स्कूल-संस्थाओं तक ही पहुँचाने की कोशिश की जाती है। गाँव को आज विकासोन्मुख करना है तो प्रत्येक गाँव में स्कूल खोलने की बात सोची जा रही है। स्कूल ग्राम-संस्थाओं की उस तिपाई का तीसरा चरण है जिस पर नवभारत की सुदृढ़ इमारत खड़ी की जा रही है। इस तिपाई के दो अन्य चरण ग्राम-पंचायत और सहकारी संस्था है।

इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में एक प्रकार का कायापलट कर देना। ये तीनों ही संरथाएँ एक दूसरे की पूरक हैं और एक ही सामुदायिक जीवन का विकास तीनों की प्रेरक शक्ति है।

विद्यालय एक छोटा समुदाय है, जो स्कूल के बाहर के समुदाय को सभी प्रकार से प्रभावित कर सकता है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के स्वरूप जीवन में विद्यालय एक अनुकरणीय दृष्टितं प्रस्तुत करता है। विद्यालय वस्तुतः ग्राम जीवन की विशेषता: सांस्कृतिक क्षेत्र में धुरी बन सकता है। विद्यालयों को राष्ट्रीय संस्कृति की व्याख्या और संचार के लिए प्रभावकारी ऐजेन्सी बनना है जो गाँव में सामाजिक क्रान्ति को अग्रसर करने में विद्यालय की प्रभावशाली सेवाएँ कर सकता है। सभी जातियों और धर्मों के विद्यार्थी यहाँ एकत्र होते, खेलते एवं विद्याध्ययन करते हैं। विद्यालय केवल निरक्षता निवारण का ही उन्मूलन नहीं करता, बल्कि ज्ञान को व्यापक रूप में फैलाने में सहायक होता है।

**5. ग्रामीण विकास में संचार-साधन के रूप में पुस्तकालय का स्थान—** आज भारत स्वतन्त्र है। राष्ट्र के चतुर्मुखी विकास के लिए सभी श्रेणी के पुस्तकालयों का वैज्ञानिक रीति से संगठन और संचालन होना चाहिये। आज के प्रगतिशील संसार में पुस्तकालय का विषय उपेक्षणीय है। समग्र विकास के दृष्टिकोण से जो भी अनुसंधान किये जा रहे हैं, उससे सम्बन्धित जानकारी की पुस्तकें हो। इसके अलावा देश में चल रहे वर्तमान अभियान की तुरन्त जानकारी के लिए रेडियों तथा अन्य चीजों का भी प्रबन्ध होना चाहिए।

स्त्री-शिक्षा, गृह-विज्ञान-स्वास्थ्य एवं सफाई सम्बन्धी छोटी-छोटी पुस्तकों की व्यवस्था हो। छोटी-छोटी पैम्फलेटों, बुलेटिनों एवं पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था भी अनिवार्य है। लोकगीत, लोकरंजन-कला, नाटक, प्रहसन आदि का भी समावेश उपयोगी होगा। जिससे सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है।

**6. ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की संचार के रूप में भूमिका—** वर्तमान शासनकाल में गठित पंचायतों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि पंचायतें गाँवों में एक प्रजातांत्रिक ढाँचे के रूप में हैं। प्रजातन्त्र क्या है, इसका स्वरूप क्या होता है तथा इसकी शासन पद्धति क्या है, यह पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों को आसानी से समझाया जा सकता है। जब ग्रामीण अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और उनके बोट द्वारा लोग पंचायत की सदस्यता प्राप्त करते हैं तो पंचायत गठित होने पर वे गाँव सम्बन्धी समस्याओं के समाधान का प्रयत्न करते हैं और शासन सम्बन्धी सही बातें लागू करते हैं। इसके द्वारा ग्रामीणों को ज्ञात होता है कि जनतन्त्र से सरकार किस प्रकार मतदान द्वारा बनायी जा सकती है तथा शासन किस प्रकार चलाया जाता है। इस प्रकार पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों को ज्ञात होता है कि जनतांत्रिक सरकार किस प्रकार गठित होती है व शासन सूत्र किस प्रकार से संचालि किया जा सकता है।

वैधानिक दृष्टि से भी विचार करने पर ज्ञात होता है कि पंचायतें संचार साधन के रूप में काफी उपयोगी हैं। पंचायत गाँव में शासन की एक इकाई के रूप में है। इस कारण समय-समय पर सरकार अपनी जो नीति निर्धारित करती है तथा ग्रामवासियों के हित में जो कानून आदि बनाती है, वह पंचायत के माध्यम से गाँवों में लागू करती है।

**7. प्रशिक्षण—** स्वतन्त्रता के बाद भी प्रशिक्षण प्रणाली चली आ रही है। वर्तमान समय में तो प्रत्येक कार्य के लिए प्रशिक्षण आवश्यक

है। आज प्रशिक्षण एक ऐसा संचार माध्यम बन चुका है जिसके अभाव में ग्रामीण विकास कदापि सम्भव नहीं हो सकता इसीलिए अब क्षेत्रीय नियोजन संस्था और ग्राम स्वराज्य विद्यालय के माध्यम से क्रमशः सहायक संगठकों एवं ग्राम सहायकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान प्रशिक्षण पद्धतियों, जैसे कक्षीय अध्यापन एवं परीक्षा के अतिरिक्त रचनात्मक उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए प्रशिक्षणार्थियों को ऐसा प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन मिलना चाहिए जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में वास्तविक समस्याओं का निराकरण करते हुए कार्यक्रम सफल बनाने में उपयोगी सिद्ध हो सके। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह होगी कि सहायक संगठनों एवं ग्राम सहायकों में प्रशिक्षण से ऐसी प्रभावपूर्ण शक्ति जागृत हो जाये, जिससे वे गाँव के लोगों की आत्मशक्ति जागृत करके उनमें इतनी क्षमता उत्पन्न कर सकें कि वे समग्र विकास योजना के माध्यम से स्वावलम्बी हो सकें।

स्वतन्त्रता के पश्चात हमारे भारतीय संचार साधनों पर ध्यान दिया गया क्योंकि संचार किसी भी राष्ट्र के विकास की प्रथम कड़ी है। भारत तो वैसे ही ग्रामों का देश है इसलिये यहाँ तो जनसाधारण तक सरकार की बात पहुँचाने के लिए अच्छे संचार साधनों की आवश्यकता है। स्वतन्त्रता के पश्चात् संचार साधनों में काफी परिवर्तन हुआ है अब इन संचार साधनों में रेडियो, समाचारपत्र, संगठन, पुस्तकालय, विद्यालय, ग्राम पंचायत, प्रशिक्षण आदि का महत्व बढ़ गया है।

इन समस्त संचार साधनों का महत्व ग्रामीणों के लिये निम्न प्रकार से हो सकता है

1. रेडियो स्वतन्त्रता से पूर्व कम लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी क्योंकि ग्रामीणों के पास धन की कमी थी लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात् रेडियो की माँग बढ़ती गई और फिर रेडियो एक अच्छे संचार साधन के रूप में विकसित हो गई।
2. समाचार पत्रों की स्थिति स्वतन्त्रता से पूर्व ठीक नहीं थी अंग्रेजों का इस पर प्रभुत्व था लेकिन आज समाचार पत्र सबकी आवश्यकता बन गया है।
3. संगठन पहले भी बनाए जाते थे लेकिन उन्हें सफल करने के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते थे लेकिन आज प्रत्येक कार्य के लिये संगठन बनाना जरूरी है अन्यथा वह कार्य सफल नहीं होगा।
4. पहले गाँव में पाठशालाएँ होती थीं जो संचार का साधन होती थीं जो ग्रामीणों को ज्ञान देती थीं लेकिन आज पाठशालाएँ तो हैं ही, साथ-साथ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
5. पुस्तकालयों के द्वारा भी ज्ञान दिया जाता था लेकिन यह कुछ ही लोगों के लिये था क्योंकि स्वतन्त्रता से पूर्व पढ़े-लिखे लोग कम होते थे लेकिन आज पुस्तकालय हमें प्रत्येक ज्ञान के लिये पुस्तक उपलब्ध कराता है।
6. जहाँ तक ग्राम पंचायतों की बात है ग्राम पंचायत प्राचीन काल से चली आ रही है और वर्तमान में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और ग्रामीण विकास का एक अच्छा साधन है।
7. प्रशिक्षण के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कार्यकुशल बनाया जा सकता है। स्वतन्त्रता से पूर्व भी लोगों को कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था पर यह तब सूक्ष्म रूप में था लेकिन आज हम सभी कार्यों के लिए प्रशिक्षित होते रहते हैं। प्रशिक्षण भी संचार का अच्छा साधन है।

ग्रामीण विकास में कुछ नये संचार साधन— स्वतन्त्रता के बाद से भारत में नई तकनीकी साधनों का आगमन प्रारम्भ हो गया था जिनका प्रयोग विकास कार्यों के लिये किया जाता था जिसमें टेलीविजन, कम्प्यूटर, इन्टरनेट एवं ई-मेल इत्यादि हैं जिनके

द्वारा विकास कार्यों की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है—  
**1. टेलीविजन:** टेलीविजन विगत तीन चार दशकों की ही उपलब्धि है। दूर तक तस्वीरों को प्रसारित करने (या कहे कि जमसमअपेपदह करने) की युक्ति 1890 ई० में ही ज्ञात हो चुकी थी परन्तु संसार का पहला नियमित टेलीविजन प्रसारण सार्वजनिक स्तर पर 1936 में हुआ।

भारत में प्रथम प्रायोगिक टेलीविजन केन्द्र का उद्घाटन 15 सितम्बर 1959 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के हाथों सम्पन्न हुआ। टेलीविजन पर जिन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था वे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित होते थे क्योंकि भारत गाँवों का देश है। टेलीविजन पर विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाताय जैसे कृषि—दर्शन, ग्रामीण—भारत, चर्चा तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम, जिनके द्वारा ग्रामीणों को वास्तविकता का ज्ञान होता है का प्रसारण किया जाता टेलीविजन कार्यक्रमों के सफल होने का एक मुख्य कारण यह भी था कि इसमें आवाज के साथ चित्र भी दिखाई देते हैं जिससे अनपढ़ व्यक्ति भी इन्हें देखकर समझ सकते हैं। इसीलिए आज टेलीविजन शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी सूचना प्रसारित करने का एक बड़ा साधन है जो विकास के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करता है।

**2. कम्प्यूटर:** भारत में कम्प्यूटर का प्रवेश 1950 में इकाई संसाधन मशीनों तथा डेस्क टॉप कम्प्यूटर्स के रूप में हुआ। हम आज जो उन्नत कम्प्यूटर देख रहे हैं उसकी प्रारम्भिक रूपरेखा 1642 में 18 वर्षीय वैज्ञानिक प्लेज पास्कल ने एक यान्त्रिक संगणक के रूप में प्रस्तुत की थी। इस यन्त्र का नाम पास्कल रखा गया था लेकिन अब जिन कम्प्यूटर्स का प्रयोग किया जा रहा है वह चौथो चरण के हैं जो सन् 1971 में विकसित हुए।

आज कम्प्यूटर्स ग्रामीण क्षेत्रों तक आसीन से पहुँच चुके हैं जिसका पूरा लाभग्रामीण जनता प्राप्त कर रही है। हम कम्प्यूटर को इन्टरनेट के साथ जोड़कर विश्व की बड़ी से बड़ी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पूरे संसार से जुड़ सकते हैं। विश्व के देशों के गाँवों की प्रगति को हम आसानी से जान सकते हैं। कम्प्यूटर एक ऐसा साधन हो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता का रूप लेता जा रहा है। आज एक सामान्य व्यक्ति भी अपना पूरा लेखा—जोखा कम्प्यूटर की सहायता से संग्रह करके रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसको खोल कर पुनः देख सकता है। यहाँ समय की बचत होती है जो हम किसी अन्य कार्य पर लगाकर अधिक धन कमा सकते हैं और अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं।

**3. इन्टरनेट:** इन्टरनेट एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें करोड़ों कम्प्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं तथा यह डिजिटल स्रोत और रिसीवर को जोड़ने की प्रक्रिया है। इन्टरनेट को सामान्यतया कम्प्यूटरों के विश्वव्यापी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक प्रोटोकोल (सूचना के आदान—प्रदान सम्बन्धी नियम) के आधार पर संचार करते हैं। इन्टरनेट के माध्यम से विविध स्रोतों से सूचनाओं को बाप्त किया जाता है जिससे विश्व में होने वाले विकास की भी जानकारी मिलती है जिससे हम अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो पिछड़े हुए हैं उनका सही रूप में विकास र सके।

**4. ई—मेल:** सूचना सम्प्रेषण का एक रूप है। इस प्रणाली में नेटवर्क के द्वारा क कम्प्यूटर को दूसरे कम्प्यूटर से जोड़कर तत्काल सूचना को सम्प्रेषित करने की सुविधा प्राप्त की जाती है। एक कम्प्यूटर से भेजी गयी सूचना को दूसरे कम्प्यूटर पर पढ़ा जा सकता है। ई—मेल प्रणाली में मोडेम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब एक कम्प्यूटर सुदूरवर्ती दूसरे कम्प्यूटर तक सूचना भेजता है, तो पहले कम्प्यूटर के साथ संलग्न

मोडेम कम्प्यूटर में भण्डारित डिजिटल सूचना कोड को टेलीफोन लाइन द्वारा एनलॉग रूप में परिवर्तित कर दूसरे कम्प्यूटर तक भेजता है। ई—मेल करने के लिए दूसरे व्यक्ति के पते की जानकारी होनी चाहिये। ई—मेल भारत में नई प्रौद्योगिकी है जिसका प्रयोग सर्वाधिक ऑटो—मोबाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। भारत में ई—मेल से अधिक तीव्रगति से संदेश पहुँचाने वाली वर्तमान में कोई सेवा नहीं है। इस सेवा का प्रयोग अभी शहरों तक ही सीमित है परन्तु शहरों में ई—मेल से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् वह गाँवों में अन्य संचार के साधनों के द्वारा पहुँच जाती है। जिससे ग्रामीण वर्तमान जानकारियों से अपना विकास आसानी से कर सके।

सभी संचार साधनों की भूमिका समय के अनुसार व स्थितियों, उपलब्ध साधनों के कारण बदलती रहती है। संचार साधनों के साथ—साथ ग्रामीण विकास की सफलता वस्तुतः सरकार की सफलता है। सरकार के पास सर्वाधिक संसाधन है जिससे वह ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन सकती है। जरूरत है सिर्फ कुछ नीतियों में परिवर्तन और उसी के अनुरूप इच्छाशक्ति, राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारी तन्त्र दोनों स्तर पर कठिन परिश्रम की ओर तथा—साथ अच्छे संचार साधन की जो ग्रामीणों तक सूचनाओं को सही रूप में संचारित कर सके। तभी ग्रामीण विकास के सपने को पूरा किया जा सकता है।

### सन्दर्भ

1. अमर कुमार जैन, ग्रामीण विकास, कुरुक्षेत्र, नवम्बर, 2012
2. डॉ० रमेश चन्द्र त्रिपाठी, पत्रकारिता— सिद्धान्त एवं स्वरूप, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1995
3. जी०एस० वर्मा, शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्धन, लॉयल बुक डिपो, मेरठ, 2005
4. एन०सी० पन्त, जनसम्पर्क, विज्ञापन एवं प्रसार माध्यम, तक्षशिला प्रकाशन, 2004
5. ओमप्रकाश सिंह, संचार के मूल सिद्धान्त, वलासिकल पब्लिशिंग कम्पनी नई दिल्ली, 2002
6. प्रौ० हरिमोहन, सूचना प्रौद्योगिकी और जन—माध्यम, तक्षशिला प्रकाशन नई दिल्ली, 2002
7. राजेन्द्र सिंह, ग्रामीण राजनीतिक अभिजन तथा ग्रामीण विकास, वलासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1996
8. श्याम चरण दूबे, संचार और विकास, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, 1974
9. सुगतदास गुप्ता, कम्प्यूनिकेशन और ग्राम्य विकास, गाँधी विद्या संस्थान, राजघाट, वाराणसी, 1967
10. श्रीमती आर०को० रावत एवं डॉ० को० गुप्ता, शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकताएँ और प्रबन्धन, राधा प्रकाशन मन्दिर, आगरा, 2006
11. एस० सी० जैन, “ग्रामीण विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रम”, योजना, अक्टूबर 2012
12. शिव शंकर सिंह, भारत में समन्वित ग्रामीण विकास एवं नियोजन, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली
13. सतीश कुमार, संगठन की उपयोगिता, योजना, नवम्बर, 2005

### Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.